

केंद्र का पैसा जनता तक नहीं, टीएमसी के पास जा रहा: पीएम मोदी

कोलकाता, 22 अगस्त। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में विभिन्न मेट्रो रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि जेसोर रोड मेट्रो स्टेशन से नोआपाड़ा-जय हिंद विमानबंदर मेट्रो सेवा और सियालदह-एस्प्लेनेड मेट्रो सेवा और बेलेघाटा-हेमंत मुखोपाध्याय मेट्रो सेवा को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही मोदी ने मेट्रो की सवारी की और मेट्रो परियोजनाओं में शामिल स्कूली छात्रों और निर्माण श्रमिकों से बातचीत की। इस दौरान मोदी ने कहा कि आज एक बार फिर मुझे पश्चिम बंगाल में विकास को गति देने का अवसर मिला... सभी खुश हैं कि कोलकाता के सार्वजनिक परिवहन में प्रगति हुई है... मैं इन विकास परियोजनाओं के लिए कोलकाता के लोगों को बधाई

देता हूँ।

वहीं, कोलकाता में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं ऐसे समय में आया हूँ जब दुर्गा पूजा की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। बड़ा बाजार से लेकर पार्क स्ट्रीट तक, कोलकाता इस उत्सव की तैयारी और सजावट में व्यस्त है। खुशी और आस्था के इस उत्सव में जब विकास का उत्सव भी जुड़ जाता है, तो खुशी दोगुनी हो जाती है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। इसलिए जब तक पश्चिम बंगाल का सामर्थ्य नहीं बढ़ेगा, तब तक विकसित भारत की यात्रा सफल नहीं हो पाएगी। क्योंकि भाजपा मानती है, भाजपा की श्रद्धा है - जब बंगाल का उदय होगा, तभी विकसित भारत



बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 11 वर्षों में केंद्र की इखट सरकार ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए लगातार हर प्रकार की मदद दी है। बंगाल में नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए जितना पैसा कांग्रेस की वड्ड सरकार ने अपने 10 साल में दिया था। उससे 3 गुना से ज्यादा पैसा हमारी भारत सरकार ने बंगाल को

दिया है। रेलवे के लिए भी बंगाल का बजट पहले की तुलना में तीन गुना बढ़ाया गया है। लेकिन, बंगाल में विकास कार्यों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये कि बंगाल के लिए जो पैसा हम राज्य सरकार को सीधे भेजते हैं... उसका ज्यादातर हिस्सा यहां लूट लिया जाता है। वो पैसा लूट का डर पर खर्च होता है। इसलिए

गरीब कल्याण की अनेक योजनाओं में बंगाल... देश के दूसरे राज्यों से पिछड़ा हुआ है।

मोदी ने कहा कि कुछ साल पहले पड़ोस में असम और त्रिपुरा के भी यही हाल थे। लेकिन सबसे असम और त्रिपुरा में भाजपा सरकार बनी है, गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ वहां जनता को मिलने लगा है। आज इन राज्यों में हर घर जल का काम तेजी से चल रहा है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज हर गरीब को मिल रहा है। गरीबों के पक्के घर बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी जनता तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जरूरी है कि यहां भी भाजपा सरकार होनी चाहिए। ये अब तय है - टीएमसी जाएगी, भाजपा आएगी।

ईडी ने अवैध सट्टेबाजी मामले में कर्नाटक के विधायक के खिलाफ छापे मारे



बेंगलुरु, 22 अगस्त। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कथित अवैध सट्टेबाजी से जुड़े धन शोधन मामले में कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के सी वीरेंद्र पप्पी, उनके भाई और कुछ अन्य के खिलाफ कई राज्यों में छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

वीरेंद्र (50) चित्रदुर्ग विधानसभा सीट से विधायक हैं। राज्य विधानसभा सत्र के अंतिम दिन हुई ईडी की कार्रवाई पर विधायक की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले, बेंगलुरु और हुबली, जोधपुर (राजस्थान), मुंबई और गोवा में कम से कम 30 स्थानों पर धन शोधन रोकथाम

003, रत्ना गेमिंग आदि जैसी ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइट संचालित करने का आरोप है और उनके भाई के सी थिपेस्वामी पर दुबई से डायमंड सॉफ्टवेयर, टीआरएस टेक्नोलॉजीज और प्राइम9 टेक्नोलॉजीज नामक तीन व्यापारिक संस्थाओं को संचालित करने का आरोप है। ये संस्थाएं वीरेंद्र की कॉल सेंटर सेवाओं और गेमिंग व्यवसाय से संबंधित हैं। एजेंसी सूत्रों के अनुसार, बेंगलुरु में कुसुमा एच के भाई अनिल गौड़ा नामक व्यक्ति के परिसरों पर भी छापेमारी की गई। कुसुमा ने कांग्रेस के टिकट पर राजराजेश्वरीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन असफल रहे थे।

पारित सभी विधेयक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण होंगे: सांसद संतोष पांडेय

रायपुर, 22 अगस्त। भाजपा मुख्य प्रवक्ता एवं सांसद संतोष पांडेय ने एकात्म परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में संसद के भीतर हुई चर्चा हमेशा महत्वपूर्ण होती है लेकिन कांग्रेस हमेशा अपने स्वार्थ सिध्दी के लिए ही सदन में चर्चा पर शामिल नहीं होती है। यह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हम जब प्रतिपक्ष में थे सार्थक चर्चाओं से सदन की गरिमा को और मजबूत बनाकर राष्ट्र हित में अपनी महती भूमिका निभाते रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदन में हो रहे गंभीर चर्चाओं में हिस्सा लेने के बजाय अपने कथित प्रयासों से देश को भ्रमित करने का काम करती है जिसे देश की



जनता भलिभाति समझती है। सांसद पांडेय ने कहा कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक चला। इस दौरान कुल 21 बैठकें हुईं। सत्र में 14 विधेयक लोकसभा में पेश किए गए, एक विधेयक वापस लिया गया और 12 विधेयक लोकसभा पारित हुए। इस दौरान विपक्ष ने सदन चलने नहीं दिया। बार-बार के

व्यवधानों के चलते सदन का सत्र प्रभावित रहा। जिसमें 130 घंटे के कुल समय में से केवल 37 घंटे ही कार्यवाही हो पाई। सांसद पांडेय ने कहा कि लोकसभा में मानसून के दौरान कई अहम विधेयक पारित किए गए, जिनमें आयकर (संशोधन) विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल संचालन विधेयक 2025, ऑनलाइन गेमिंग (प्रोत्साहन और विनियमन) विधेयक 2025, सहित कुल 12 विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि यह सभी विधेयक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण फैसले होंगे।

काशी विद्यापीठ के कुलपति पर अभद्र भाषा, दबाव और पक्षपात के गंभीर आरोप सुरेश गांधी

वाराणसी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की गरिमा तब आहत होती है जब वहां एक विधवा कर्मचारी को अभद्र भाषा, धमकियों और दबाव के बीच इस्तीफा देना पड़ता है। कुलपति का पद विश्वविद्यालय की मर्यादा और शुचिता का प्रतीक है, लेकिन यदि वह किसी अतिथि प्रवक्ता को बचाने के लिए अपने कर्तव्य की सीमाएं लांघते हैं, तो यह प्रशासनिक विफलता की स्पष्ट मिसाल है। अब जब मामला राजभवन तक पहुंच चुका है, तो



जरूरत है निष्पक्ष जांच और कड़े कदम की। यह सिर्फ शिखा बंसल का मामला नहीं, बल्कि पूरे विद्यापीठ की साख और नैतिकता का प्रश्न है। बता दें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में कुलपति प्रो. आनंद कुमार त्यागी पर लगाए गए आरोपों ने विश्वविद्यालय के

वातावरण को हिला कर रख दिया है। विश्वविद्यालय की वरिष्ठ सहायक (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) शिखा बंसल, जो दिवंगत प्रोफेसर की विधवा हैं, ने कुलपति द्वारा अभद्र भाषा और दुर्व्यवहार से आहत होकर 19 अगस्त को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा अब तक

स्वीकार नहीं हुआ है, लेकिन पीड़िता पर लगातार दबाव और धमकियों का सिलसिला जारी है। भय और अपमान से टूटी शिखा बंसल घर छोड़कर अज्ञात स्थान पर जाने को मजबूर हो गई हैं। कैंपस में उठे सवाल की डोर पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग से जुड़ी है। 11 अगस्त को हुए अतिथि प्रवक्ता पद के इंटरैक्शन में डॉ. रमेश कुमार सिंह भी शामिल हुए थे। आरोप है कि वे खुद को कुलपति का करीबी बताते हैं और उनके नाम पर धन उगाही तक करते हैं। इतना ही नहीं, गोपनीय विभाग की सूची में उन्हें सहायक कुलानुशासक के रूप में दर्ज भी कर दिया गया, जबकि नवीनीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। डॉ. रमेश ने शिखा बंसल पर परिणाम समय से पहले

बताने का दबाव बनाया। मना करने पर धमकी दी और सीधे कुलपति के पास शिकायत करने पहुंच गए। सूत्रों के अनुसार, कुलपति कक्ष में शिखा बंसल को बुलाकर उन्हें डांटा गया और अपमानजनक भाषा का प्रयोग हुआ। मौके पर मौजूद रमेश सिंह ने भी अपशब्द कहे और नौकरी छोड़ने तक की धमकी दी। कुलपति ने तंज कसते हुए कहा, कुछ आता-जाता नहीं, मृतक आश्रित में नौकरी मिल गई है तो बहुत काबिल बन रही हो। आहत शिखा बंसल ने उसी समय इस्तीफा भेज दिया। इस्तीफे में कुलपति की अभद्र भाषा का उल्लेख भी है।

इस्तीफे के बाद शिखा बंसल पर इस्तीफा वापस लेने का दबाव डाला गया।

बिहार एसआईआर में आधार कार्ड या 11 अन्य दस्तावेज मान्य, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को बड़ा आदेश

नई दिल्ली, 22 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनावी राज्य बिहार में चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान में बदलाव करने से इनकार कर दिया, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को निर्देश दिया कि वह सूची से बाहर किए गए मतदाताओं को ऑनलाइन माध्यम से दावे दाखिल करने की अनुमति दे, साथ ही भौतिक रूप से भी दावा पेश करने की अनुमति दे। अदालत ने निर्वाचन आयोग को मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए 11 दस्तावेजों या आधार कार्ड को स्वीकार करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति

जॉयमाल्या बागची की दो सदस्यीय पीठ ने राजनीतिक दलों को उन 65 लाख लोगों की मदद करने का भी निर्देश दिया, जिन्हें मसौदा मतदाता सूची से बाहर रखा गया है। अदालत ने कहा, सभी राजनीतिक दल अगली सुनवाई तक उस दावा प्रपत्र पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे उन्होंने बहिष्कृत मतदाताओं द्वारा दाखिल करने में मदद की थी। मामले की अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि केवल दो आपत्तियाँ उठाई गईं, जबकि राजनीतिक दलों के 1.60 लाख से अधिक बूथ-स्तरीय एजेंट (बीएलए) हैं। सुनवाई के दौरान,



चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि उसे यह साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाए कि कोई भी मतदाता सूची से बाहर नहीं है। आयोग ने अदालत को यह भी बताया कि 85,000 बहिष्कृत मतदाताओं ने अपने दावा पत्र जमा कर दिए हैं, जबकि दो लाख से ज्यादा नए मतदाता मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के

लिए आगे आए हैं। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने अदालत से कहा, राजनीतिक दल शोर मचा रहे हैं और हालात इतने खराब नहीं हैं। हम पर विश्वास रखें और हमें कुछ और समय दें। हम आपको दिखा देंगे कि कोई भी मतदाता सूची से बाहर नहीं है। बिहार में जहाँ इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर अभियान चलाने के फैसले से भारी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। एसआईआर के अनुसार, बिहार में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या इस अभियान से पहले के 7.24 करोड़ से घटकर 7.9 करोड़ रह गई है।

महाराजगंज में खेत में सिंचाई करते समय करंट लगने से पिता-पुत्र की मौत ठूठीबारी। महाराजगंज जिले के ठूठीबारी थाना क्षेत्र के एक गांव में शुक्रवार को सुबह खेत में सिंचाई करते समय एक व्यक्ति और उसके युवा बेटे की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। ठूठीबारी थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) महेंद्र मिश्रा ने बताया थाना क्षेत्र के सुकरहर गांव के निवासी श्रीकांत यादव (60) और उनका बेटा संतोष यादव (25) शुक्रवार को सुबह सुबह खेत में सिंचाई करने गए थे। पानी के पंप से जुड़े बिजली के तार के संपर्क में आने से उन्हें करंट लग गया और दोनों की मौत हो गई।



मोहम्मद दानिश
जिला पंचायत सदस्य
वार्ड न0 10
के भावी प्रत्याशी



NEW LIGHT CLASSES
TRADITION OF EXCELLENCE

2nd Floor, Sheetal Bldg.
Near Diamond Talkies,
L. T. Road, Borivali (West)
Mumbai - 400 092
Maharashtra

ADMISSIONS OPEN
ALL OVER INDIA
ENROLL NOW



SMART CLASSROOM

(ONLINE/OFFLINE)
Courses Offered

- Std. XI & XII (Sci.)
- NEET
- JEE (Main & Advance)
- MHT-CET
- Polytechnic & Engg
- Physics and Maths (ICSE, CBSE, ISC)

M: 9833240148 | E: edu@newlightclasses.com | W: www.newlightclasses.com

